जो सिरफिरे होते है वहीं इतिहास लिखते है, समझदार लोग तो बस उनके बारे में पढ़ते है।
– अज्ञात

इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट

यह एक अभूतपूर्व गठबंधन है, जब सूचना ,कम्युनिकेशन और डिजिटल पेमेंट के इतने बड़े दायरे में एक ही खिलाड़ी का दबदबा होगा। हालांकि इस साझीदारी को भारत के राष्ट्रीय हित में दिखाया जा रहा है और किसानों, छोटे व्यापारियों से लेकर सभी भारतवासियों की जिंदगी सुधारने का दावा किया जा रहा है।

रिचा शर्मा।

दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क कंपनी फेसबुक ने रिलायंस जियो प्लैटफॉर्म में 43,574 करोड़ रुपये लगाकर दस फीसदी हिस्सेदारी लेने का ऐलान किया है। फेसबुक ने माइनॉरिटी हिस्सेदारी के लिए दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं किया। इससे पता चलता है कि भारत के टेलिकॉम सेक्टर की उसके लिए कितनी अहमियत है।

भारत की पहले नंबर की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क कंपनी का एक मंच पर आ जाना गहरे मायने रखता है। इसमें यह भी जोड़ दें कि फेसबुक की मिल्कियत वाले व्हाट्सऐप के लिए भी भारत सबसे बड़ा बाजार है जहां 40 करोड़ कस्टमर और 80 पर्सेंट मोबाइल फोन उससे जुड़े हैं। व्हाट्सऐप जल्द ही अपनी पेमेंट सर्विस लाने की तैयारी में है, जो अब जियो की साझीदारी में सामने आएगी। यह एक अभूतपूर्व गठबंधन है, जब सूचना ,कम्युनिकेशन और डिजिटल पेमेंट के इतने बड़े दायरे में एक ही खिलाड़ी का दबदबा होगा। हालांकि इस साझीदारी को भारत के राष्ट्रीय हित में दिखाया जा रहा है और किसानों, छोटे व्यापारियों से लेकर सभी भारतवासियों की जिंदगी सुधारने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जितनी बड़ी यह डील है, उतने ही बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं।

देश हित में यह जरूरी है कि इस साझेदारी को तटस्थता से समझा जाए और सभी पक्षों पर विचार हो। जैसे सबसे पहले इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि इनफॉर्मेशन और मीडिया सेक्टर में मोनोपोली का जो माहौल बनेगा उससे कैसे निपटा जाएगा?

यहां सवाल डेटा और प्राइवेसी का है। जियो और फेसबुक? व्हाट्सऐप के पास पहले ही हमारी जिंदगी का इतना डेटा है कि उसकी हिफाजत का सवाल अपने जवाब का इंतजार कर रहा है। डेटा प्राइवेसी के मामले में फेसबुक का क्या रिकॉर्ड है और किस तरह दुनिया भर में वह लोकतांत्रिक सरकारों के निशाने पर है यह सभी जानते हैं। उसी के चलते फेक न्यूज का दानव इंसानियत के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन चुका है। जल्द ही इसमें व्हाट्सऐप की पेमेंट सर्विस का पहलू भी जुड़ जाएगा। हम साफ देख सकते हैं कि एक बेहद जटिल सवाल हमारे आगे खड़ा हो रहा है जिसका माकूल जवाब तलाशे बिना हमारे रेगुलेटर्स को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इससे जुड़ा अगला सवाल यह है कि क्या यह नई ताकत जिम्मेदारी से व्यवहार करेगी? दूसरी डिजिटल पेमेंट कंपनियों को मुकाबले से हटाने की कोशिश तो नहीं होगी? ताकत का इतना बड़ा केंद्रीकरण ऐसी आशंकाएं पैदा कर सकता है। कौन इस बात की गारंटी लेगा? रेगुलेटर्स अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

जाहिर है, ये सभी मुद्दे भारतीय जनता की डिजिटल आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों से ताल्लुक रखते हैं। ये सिर्फ किसी कंपनी या बिजनेस के मुद्दे नहीं हैं। इस मौके को कुछ सबसे जरूरी मुद्दों से मुठभेड़ के तौर पर देखा जाना चाहिए। दुनिया की हर समझदार सरकार ऐसा करती रही है।

आदर मान

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। अब आप सोच रहे हैं कि यह तो अच्छी बात है। इतना आदर मान तो किस्मत वालों को मिलता है। नवरत्न जी तो पूरे राजसी स्वाद ले रहे हैं तो मुझे जलन सी क्यों हो रही है। अब मेरा जवाब भी सुन लीजिए। लोकडाउन से पहले राजसी स्वाद लेने वाले नवरत्न जी का दिल का दर्द अब रुलाने वाला है। शुक्रवार देर शाम खाना खाने के बाद छत पर टहलने गया तो जो सामने की दूसरी मंजिल पर जो मैंने देखा वो हैरान करने वाला था। हर समय टिपटॉप रहने वाले नवरत्न जी पायजामा बनियान में पसीना–पसीना थे। हाथ में झूठी थाली रसोई की तरफ जा रहे थे। मैंने सोचा कि रसोई की तरफ जा रहे होंगे सो ये बर्तन उठा लिए होंगे। इतने में उनकी श्रीमती जी की आवाज सुनाई पड़ी। दो थाली और रह गई है उन्हें भी ले जाना।

संपादकीय

जिंदगी का महत्व

अमेरिका में कोरोना से संक्रमित मरीज के इलाज का औसत खर्च 30,000 डॉलर यानी लगभग 22 लाख रुपये आंका गया है। यह पूरा खर्च सरकार वहन करेगी या फिर कुछ हफ्तों और महीनों के बाद अस्पताल का बिल मरीज के घर पहुंच जाएगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस वायरस ने एक बात और साफ कर दी कि अमेरिकी स्वास्थ्य तंत्र का मौजूदा ढांचा इस तरह की महामारी का सामना कर पाने में अक्षम है। देश के कई इलाकों में अस्पतालों में बिस्तरों और डॉक्टरों की संख्या घटती गई है क्योंकि उनके मुनाफे पर असर पड़ रहा था।

इतनी भारी संख्या में हुई मौतों के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप रोज अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मौतों की कुल संख्या विशेषज्ञों के पहले लगाए अनुमान से काफी कम है। न्यूयॉर्क के गवर्नर की दलील है कि काले और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों में ज्यादा मौतें इसलिए हुई हैं क्योंकि अनिवार्य सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में उनकी संख्या ज्यादा है। इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले 3.5 ट्रिलियन डॉलर के सालाना खर्च का सिर्फ ढाई प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है। एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य तंत्र, जहां हर नागरिक जब चाहे तब इलाज करवा सके, जहां इंश्योरेंस कंपनियों के फायदे से ज्यादा लोगों की जिंदगी को महत्व दिया जाए, इसपर आज भी कोई बहस नहीं हो रही है। जब हालात सामान्य थे, तब भी करोड़ों अमेरिकी इस घोर पूंजीवादी व्यवस्था में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। अर्थव्यवस्था पर इसका परोक्ष असर तो था लेकिन सीधा असर नहीं नजर आता था।

यह सोचकर कि शायद यह दोनों की आखिरी बातचीत हो। लेकिन उस दम तोड़ते मरीज ने फोन पर बात करने की बजाय अपनी उखड़ती सांसों के बीच डॉक्टरों से पूछा, 'इस इलाज के पैसे कौन भरेगा?'

हेल्थ सिस्टम वर्षों से बीमार

ब्रजेश उपाध्याय

न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में कोरोना वायरस के एक मरीज की स्थिति जब गंभीर हो गई, तो डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रखने और उसके शरीर में नलियां लगाने का फैसला किया। इंट्यूबेशन या शरीर में नलियां लगाना एक तरह की आखिरी कोशिश होती है मरीज को बचाने की, और अब तक के आंकड़ों के अनुसार इसके बावजूद 80 प्रतिशत मरीजों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों ने मरीज की पत्नी को फोन लगाया। यह सोचकर कि शायद यह दोनों की आखिरी बातचीत हो। लेकिन उस दम तोड़ते मरीज ने फोन पर बात करने की बजाय अपनी उखड़ती सांसों के बीच डॉक्टरों से पूछा, 'इस इलाज के पैसे कौन भरेगा?'

मरीज का इलाज करनेवाली टीम के एक सदस्य ने फेसबुक पर लिखा– 'मरणासन्न मरीज के आखिरी शब्द यदि इलाज के खर्च के बारे में हों, तो इससे ज़्यादा हृदयविदारक और क्या हो सकता है? यह देश सही मायने में एक नाकाम राष्ट्र है।' अमेरिका की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का मात्र चार प्रतिशत है, लेकिन वहां कोविड–19 से 50,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, यानी दुनिया की कुल मौतों का लगभग 25 प्रतिशत। कोरोना के खिलाफ समय

रहते कार्रवाई न करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप पर उंगलियां उठ रही हैं। महामारियों के लिए एक कारगर राष्ट्रीय योजना की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इस दुर्दशा की जड़ में है वही सवाल जो न्यूयॉर्क के अस्पताल में उस दम तोड़ते मरीज ने पूछा था– 'इस इलाज के पैसे कौन भरेगा?'

स्वास्थ्य और बीमारियों से जुड़े शोध हों या आधुनिक अस्पताल और उपकरण, अमेरिका अव्वल नंबर पर ही आता है। लेकिन दूसरी सचाई यह भी है कि अमेरिकी स्वास्थ्य तंत्र बरसों से सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पर नजर रखता आया है। दशकों से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को नजरअंदाज किया गया है और उन पर होनेवाले खर्च में कटौती होती गई है। दुनिया में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा खर्च करनेवाले इस देश में एक बड़ा तबका स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहा है क्योंकि उसके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है।

कोरोना के बारे में अभी भी दुनिया को बहुत जानकारी नहीं है लेकिन एक बात विशेषज्ञ पहले ही बता चुके हैं कि इसकी मार सबसे ज्यादा उन पर पड़ती है जो दमा, दिल का रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं। समुचित हेल्थ इंश्योरेंस या स्वास्थ्य बीमा से पूरी तरह वंचित आबादी इन बीमारियों से ग्रस्त रहने के बावजूद इलाज को टालती रही है। बीते दिसंबर में प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले चौदह सालों में हर साल 30 प्रतिशत अमेरिकी इलाज के खर्च की वजह से अस्पताल नहीं गए हैं और 19 प्रतिशत अमेरिकी तो गंभीर बीमारियों के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। आज भी तीन अमेरिकी ऐसे हैं जिनके पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है।

इसका असर कोरोना से मरने वालों की संख्या पर साफ नजर आया है। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार कोविड–19 से मरनेवालों में अफ्रीकी–अमेरिकी यानी अश्वेतों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज़्यादा है। स्वास्थ्य बीमा से वंचित लोगों की संख्या भी इसी समुदाय में सबसे ज्यादा है। जिन इलाकों में काले बहुसंख्यक हैं, वहां श्वेत बहुसंख्यक इलाकों की तुलना में वायरस से संक्रमण की दर तीन गुना ज्यादा है और मृत्यु दर छह गुना ज्यादा।

अष्टयोग-5033

	5	2	3	7		6
6	29		40		38	1
	1	4	6		2	
2	24		34		32	4
5		3		4	7	
	31		30		32	5
7		1		2	6	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5032 का हल

7	6	4	1	5	3	2
1	34	5	28	2	29	6
4	5	2	6	3	1	7
2	31	6	33	4	28	1
5	6	1	4	7	2	3
6	33	3	33	6	34	4
3	2	7	4	1	6	5

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

मॉर्डनाइजेशन की चुनौती

मोहन। कोरोना वायरस ने दिखाया है कि बरसों से बीमार अमेरिकी स्वास्थ्य तंत्र एक आकाश चूमती अर्थव्यवस्था को भी हफ्तों में जमीन पर ला सकता है। इसके बावजूद आने वाले समय में यहां हालात बदलेंगे, स्वास्थ्य तंत्र में आंदोलनकारी बदलाव होगा, इसके आसार फिलहाल नहीं नजर आ रहे। वैसे संक्रमण में तेजी के कुछ हफ्तों बाद ट्रंप प्रशासन ने ऐलान भी किया कि जिनके पास समुचित इंश्योरेंस नहीं है या बिल्कुल भी इंश्योरेंस नहीं है उनका कोरोना वायरस का परीक्षण और इलाज मुफ्त होगा। लेकिन स्वास्थ्य तंत्र की पेचीदगियों और भारी खर्च के डर से बहुत से संक्रमित लोग अस्पताल जाने से डरते रहे और जब पहुंचे तबतक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। विशेषज्ञ कह चुके हैं कि यदि मरीज खर्च की वजह से डॉक्टर के पास जाने से या आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने से कतराए तो किसी भी महामारी से लड़ना असंभव हो जाता है।